



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 20, 2014/आश्विन 28, 1936

No. 295]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2014/ASVINA 28, 1936

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मुम्बई, 14 अक्टूबर, 2014

### अधिसूचना

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार 31 मार्च, 2005 को आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता को और विस्तारित करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

### आदेश

(अक्टूबर 2014 के 8वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 39 द्वारा 31 मार्च, 2005 को भारत के राजपत्र में 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुए थे और दिशानिर्देशों के खंड 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाए अथवा विस्तार नहीं किया जाता है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, इस प्राधिकरण ने 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया था। पिछली बार यह वैधता 30 जून, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया था और इसे राजपत्र सं. 168 द्वारा 2 जून, 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. फॉलो अप करने के बाद, पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने, अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी(पीटी-II) दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा, 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 दिसम्बर, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की थी।

4. तदनुसार, 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 दिसम्बर, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2014]

**Tariff Authority for Major Ports**

Mumbai, the 14th October 2014

**NOTIFICATION**

**No.TAMP/21/2009-WS.**—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’, the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’ notified vide Order No.TAMP/23/2003-WS on 31 March, 2005, as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**No. TAMP/21/2009 - WS**

**O R D E R**

(Passed on this 8th day of October 2014)

The ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’ were notified in the Gazette of India on 31 March, 2005 vide Gazette No. 39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts’ Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March, 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, remained in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March, 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2. As advised by the Government of India in the Ministry of Shipping this Authority extended the validity of the ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’ from time to time and the last extension till 30 June, 2014 or until further orders, whichever is earlier, was notified in the Gazette of India on 2 June, 2014 vide G.No.168.

3. After follow up, the Government of India in the Ministry of Shipping, vide its letter No. PR-14019/20/2009-PG(pt-II) dated 24 September, 2014, has extended the validity of the ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’ till 31 December, 2014 or until further orders, whichever is earlier.

4. Accordingly, the validity of the ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’ is extended till 31 December, 2014 or until further orders whichever is earlier.

**T.S. Balasubramanian**, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2014]